(ख) 1992-93 के दौरान उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1991-92 के दौरान स्वास्थ्य के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए 5.79 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई थी। वर्ष 1991-92 के दौरान साक्षरता अभियान (लाइटेन्स लर्निंग बोर्ड) पर अनुमानित खर्च 6.20 करोड़ रुपये था।

(ग) व (घ) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य को आबंटित धनराशि के इस्तेमाल की स्थिति नीचे दर्शाई गई है।

(करोड़ रुपयों में)

कार्यक्रम	आबंटन	उपयोग
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	21.32	23.08
2. जवाहर रोजगार योजना	81.89	100.39
3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	16.33	15.14

इस प्रकार, 191-92 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम को छोड़कर प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निधियों का उपयोग आबंटित राशि से अधिक हुआ है।

ग्रामीण उद्योग के लिए अपर्याप्त धनराशि

735. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए बजट वर्ष में अपर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1992-93 के दौरान इस विभाग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के जरिए योजनागत स्कीमों के तहत ग्रामीण उद्योगों के लिए 19100 लाख रु. आबंटित किए गए हैं। 1991-92 के दौरान बजट में इतना ही प्रावधान किया गया था। तथापि, पुनर्विनियोग द्वारा 1991-92 के दौरान बजट में 200 लाख रु. की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गयी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामोद्योग के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को आबंटित की गयी राशि इस प्रकार है :

वर्ष	राशि (रु. लाखों में)
1989-90	17500
1990-91	18600
1991-92	19300

उत्तर प्रदेश को भूमि सुधारों के लिये विशेष सहायता

736. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश को भूमि सुधारों के लिए विशेष सहायता प्रदान करने पर विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट-स्वामी) : (क) से (ग) राज्यों को भूमि सुधारों के लिए सहायता अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को वित्तीय सहायता देने, राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दी जाती है। तथापि, भूमि सुधारों के लिए किसी भी राज्य सरकार को कोई विशेष सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद का स्थापित किया जाना

737. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में ग्रामीण विकास की गति बढ़ाने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) सरकार के पास देश में ग्रामीण विकास की गति को तेज करने के लिए एक केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास हेतु आबंटन

738. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्रामीण विकास स्कीम के लिए आबंटित कुल वार्षिक धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह स्वीकृत धनराशि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है;

(ग) क्या यह सच है कि स्वीकृत धनराशि का वह प्रतिशत अत्यल्प है क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में धनराशि में कितनी वृद्धि किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार तथा राज्यवार आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश को प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 1992-93 के दौरान किया गया निधियों का आबंटन निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम	आबंटन
1. जवाहर रोजगार योजना	498.32
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	130.62
3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	47.24

Targets fixed under Jawahar Rozgar Yojana

739. SHRIMATI SARALA MAHESHWARI ;

SHRI MD. SALIM :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state the targets fixed under the Jawahar Rozgar Yojana during 1992-93 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI G. VENKATSWAMY) : For 1992-93, employment targets of 7762.52 lakh mandays have been fixed under Jawahar Rozgar Yojana.

Functions of the Natonal Land use and Wasteland Development Council

740. SHRI BALBIR SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what are the names of the present members of the National Land Use and Wasteland Development Council;

(b) what are its main function; and